...यह लोकतंत्र है

मीडिया का कहना है कि विकीलीक्स के ताजा खुलासे से केंद्र सरकार संकट में पड़ गई है। हमारा कहना है कि इस खुलासे से सरकार किसी भी संकट में नहीं पड़ी है। इस खुलासे में यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका के साथ परमाणु करार के मुद्दे पर जब वामपंथी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था तो अल्प मत में आ चुकी सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए सांसदों की खरीद की थी। इस संबंध में अमेरिका के भारत में प्रभारी राजदूत स्टीवन वाइट ने 17 जुलाई,2008 को अपने विदेश मंत्रालय को एक गोपनीय तार भेजा था जिसमें यह बताया गया था कि दूतावास के पॉलिटिकल काउंसलर सोनिया परिवार के नजदीकी सतीश शर्मा से मिले थे और शर्मा ने उन्हें आश्वस्त किया था कि 22 जुलाई को विश्वास मत जीतने के लिए आवश्यक प्रबंध किये जा रहे हैं। शर्मा के एक राजनीतिक सहायक नचिकेता कपूर ने अमेरिकी दूतावास को आश्वस्त करने के लिए वहां के कर्मचारियों को नोटों से भरी दो पेटियां दिखाई थीं और कहा था कि सांसदों को अपने पक्ष में करने के लिए 50-60 करोड़ रुपये का इंतज़ाम हो गया है। इसके अलावा अकाली दल के सांसदों को तोड़ने के लिए अमेरिकी व्यवसायी संत सिंह चटवाल की मदद लेने की बात कही गई है और भाजपा के सांसदों को तोड़ने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य की मदद लेने की बात कही गई है। अगर ऐसा किया गया है तो इसमें ग़लत क्या है?

इससे तो सिर्फ़ यही स्पष्ट होता है कि अमेरिका चाहता था कि किसी भी कीमत पर मनमोहन सिंह की सरकार बनी रहे, क्योंकि और किसी दूसरी सरकार से उसे उतना समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं थी जितनी कि इस सरकार से। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री अमेरिका के कहने पर बनाया गया था। इनकी वफ़ादारी पर अमेरिकी शासकों को कोई संदेह नहीं था, क्योंकि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम करने के दौरान इन्होंने अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों को भारत में लागू करवाने में बड़ी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद जब वे भारत के वित्त मंत्री बने तो उन्होंने खुल कर अमेरिकी नीतियों के पक्ष में काम करना शुरू कर दिया और नयी आर्थिक नीति जिसकी शुरुआत राजीव गांधी के शासन के दौरान ही हो गई थी, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रति इनकी 'सेवाओं' को देखते हुए अमेरिका के शासकों ने इन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति पाया। वैसे भी इन्होंने अपने ऊपर 'ईमानदारी' का मुल्लमा चढ़ा रखा था। लेकिन इन्होंने जहां तक संभव हो सकता था, देश में अमेरिकी साम्राज्यवादियों के हितों को बढ़ावा दिया और परमाणु समझौते के माध्यम से इन्होंने एक तरह से देश की संप्रभुता को भी अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया।

अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के सबसे उग्र विरोधी वामपंथी दल थे जिनके समर्थन पर सरकार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी यद्यपि परमाणु समझौते की सिद्धांतत: विरोधी नहीं थी, पर उसका दर्द यह था कि यह समझौता उसके शासन काल में न होकर मनमोहन सिंह के शासन में हो रहा है। बाकी दलों को इस मुद्दे से कोई खास लेना-देना नहीं था। यह परमाणु समझौता किस प्रकार देश की आम जनता के हितों के विरुद्ध है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। चाहे कोई भी दल हो, उसके सांसदों का हित सांसद बने रहने में था ताकि जनता को लूटने का जो मौका उन्हें मिला है, उस पर कोई आंच न आये।

आख़िर 22 जुलाई, 2008 को सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया। जाहिर है, यह काम सांसदों को खरीद कर के ही किया गया था। लेकिन ऐसा न किया जाता तो सरकार संसद में बहुमत कैसे साबित करती? इसके बाद भाजपा के कुछ नेताओं ने संसद में नोटों की गड्डियां लहराईं खरीदो-फ़रोख्त को उजागर करने के लिए। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार ने सांसदों को खरीदा है। इस मामले में सरकार यह जवाब दे सकती है कि सांसद अगर बिकने के तैयार हुए तो तभी तो उन्हें खरीदा जा सका। इसमें भला उसका क्या दोष? सत्ता हासिल करने के लिए हर तरह की तिकड़म करनी पड़ती है और उसे बचाये रखने के लिए भी। सत्ता हासिल करने के लिए पहले मतदाताओं को बहलाया-फुसलाया जाता है और पैसे भी बांटे जाते हैं। फ़िर सरकार को बचाने के लिए सांसदों को पैसे देने पड़े तो कौन-सी आफत आ गई जो अब विरोधी दल प्रधानमंत्री से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं।

सरकार को बचाने के लिए सांसदों का खरीदने का पूर्व उदाहरण मौजूद है। जब नरसिंहराव की सरकार अल्पमत में आ गई थी तो उसे गिरने से बचाने के लिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कतिपय सांसदों को करोड़ों में खरीद लिया था। फ़िर मनमोहन सिंह ने ऐसा किया तो क्या ग़लत किया? मनमोहन सिंह विद्वान और ईमानदार माने जाते हैं तो नरसिंहराव भी कोई कम विद्वान नहीं थे और बेईमान तो उन्हें किसी ने कहा ही नहीं। पर सरकार बचाने के लिए उन्होंने सांसदों को रिश्वत दी और मनमोहन सिंह ने भी सरकार बचाने के लिए सांसदों को रिश्वत दी। तो बुरा क्या किया?

हर प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य होता है कि अपनी सरकार बचाने के लिए वह कुछ भी करे। राजनीति को कुछ कवियों ने 'नंगी वेश्या' यूं ही नहीं कहा है। वेश्या पैसे लिए बिना नंगी नहीं होती, उसी प्रकार राजनीति का संचालन करने वाले सांसद भी पैसे लिए बिना नंगे नहीं होते। अब जब सत्ता का भोग करना हो तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इस पर इतनी चिल्ल-पों क्यों? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस्तीफ़ा मांगने वालों को यह सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार की रक्षा 'अनैतिक' साधनों से सिर्फ़ अपने स्वार्थ में नहीं की। उनका स्वार्थ बड़ा था। वे अमेरिकी साम्राज्यवादियों के हित में अपनी सरकार की रक्षा कर रहे थे। ऐसा करके वे अपने 'मालिकों' की सेवा कर रहे थे। एक नौकर के लिए अपने मालिक की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म की पालना के लिए उन्होंने सांसदों पर 50-60 करोड़ रुपये लुटा दिये तो कुछ भी ग़लत नहीं किया। उनके मालिक यह पैसा उन्हें मय ब्याज लौटा देंगे। उनकी सरकार बच गई और अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने बड़ा मुनाफ़े वाला सौदा कर लिया। अब वे अपने जंग खाये दो कौड़ी के परमाणु रियेक्टर झाड़-पोंछ कर, चमका कर करोड़ों डालर में भारत को बेच देंगे। जब वे इतना भारी सौदा करेंगे तो शासकों को कमीशन भी देंगे। प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, वे कमीशन नहीं लेंगे, पर उनके सहयोगी तो लेंगे ही। अमेरिका जो परमाणु रियेक्टर बेचेगा, वह चले या न चले, उसकी कोई ज़िम्मेवारी नहीं। उन रियेक्टरों से परमाणु विकिरण फैल जाये, उसकी ज़िम्मेवारी भी अमेरिका की नहीं। परमाणु विकिरण फैलेगा तो लोग़ मरेंगे तो बाद में, पहले उनकी खाल जल जायेगी। फ़िर लोग़ पीढ़ी-दर-पीढ़ी मरते रहेंगे। अमेरिका इनकी ज़िम्मेवारी नहीं लेगा। उसका काम तो परमाणु रियेक्टर बेचने के बाद खत्म हो जायेगा। हां, वह इस बात का जरूर ख्याल रखेगा कि इन रियेक्टरों की मदद से भारत कहीं और ज्यादा परमाणु बम न बना ले।

हम तो यह मानते हैं कि विकीलीक्स का खुलासा दो कौड़ी का है। इस खुलासे पर जो हंगामा मचा रहे हैं, यह उनका काम है। वे अपना काम कर रहे हैं। सरकार को अपना काम करना चाहिए। क्या भाजपा वाले दूध के धुले हैं? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो साम्राज्यवाद के हित में अपनी सरकार बचाने के लिए पैसे दे कर सांसदों को नंगा किया, पर भाजपा वाले तो निजी स्वार्थ में नंगे होते रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को जवाबी हमला बोलना चाहिए। ऐसे मौके पर 'युवराज' बड़े काम के साबित हो सकते हैं। उन्हें तुरंत किसी ग़रीब की झोंपड़ी की ओर दौड़ लगा देनी चाहिए और उसके यहां जा कर खाना खा कर उसकी टूटी चारपाई पर सो जाना चाहिए। इससे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नैतिक बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री इस खुलासे से जरा भी चिंतित न हों। विकीलीक्स के खुलासे के जवाब में कहा जा सकता है कि उसके संस्थापक और संपादक असांजे का चरित्र ठीक नहीं है। वह यौन शोषक और बलात्कारी है। बस इतना कह भर देने से उसके द्वारा किये गये खुलासे की कोई अहमियत नहीं रह जायेगी। और अगर विरोधी इस मुद्दे पर ज्यादा ही शोर-शराबा मचायें तो प्रधानमंत्री बिना घबराये संसद में बयान दे दें कि कि उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए सांसदों को खरीदा और ऐसा देश हित में किया, क्योंकि अब उनका शासन हो या भाजपा का या वामपंथियों का शासन हो जाये, देश हित अमेरिका के हित से जुड़ चुका है। उन्होंने बरसों अमेरिकी प्रभुत्व वाली संस्थाओं में काम किया है और अभी भी उसकी पेंशन खा रहे हैं, इसलिए यह बात उन्हें और उनकी (विदेशी) मालकिन सोनिया गांधी को भी अच्छी तरह पता है। सोनिया गांधी देशप्रेमी हैं, इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। आख़िर सबको पता चल गया कि कि उन्होंने अपने देशवासी हथियारों के दलाल क्वात्रोची को कानूनी शिकंजे से कैसे बचाया। अब उसका बेटा पिता के व्यवसाय में आ गया है। उसे भी वे संरक्षण दे रही हैं। अब उनका एक ही कर्त्तव्य है कि अगले चुनाव तक वे इस सरकार की नैया चाहे जैसे भी हो खेवते रहें और अगले चुनाव में जीत हासिल कर राज सिंहासन युवराज को सौंप दें।

विरोधियों से उनकी यह अपील होनी चाहिए कि वे देश में हुए अब तक के सबसे बड़े घोटाले संचार घोटाला की जांच संयुक्त संसदीय दल से करवा रहे हैं। यह सभी दलों की मांग पर हो रहा है, वरना वे और उनकी मालकिन सोनिया इस पक्ष में नहीं थे। विरोधियों को सोचना चाहिए कि पूर्व संचार मंत्री जेल में पड़ा यातना भोग रहा है। इसके अलावा आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला आदि छोटे-मोटे कितने घोटालों की जांच सरकार करवा रही है। सरकार चाहती तो इन घोटालों की जांच करवाने से मना कर देती। कौन माई का लाल कुछ कर लेता? पर यह प्रजातंत्र है। इसमें घोटाले होते हैं तो उनकी जांच भी होती है और बड़ों-बड़ों को जेल भी जाना पड़ता है। पर सांसदों को पैसे दे कर अपने पक्ष में करना कोई घोटाला नहीं है। यह तो खुला खेल है। इसलिए इस मुद्दे पर इस्तीफ़ा मांग कर डिस्टर्ब न करें। आगे जो तमाशा होता है, उसे चुपचाप देखें। भूले नहीं, यह लोकतंत्र है।

- ग़रीबदास

पाठक मंच

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। न्याय बेचने वाली निर्मल यादव कटघरे में आ ही गयी। कटघरे में तो इसे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। पर शासक वर्ग ने इसे बचाने का भरपूर प्रयास किया और एक रिश्वतखोर जज का तबादला कर उसकी नौकरी बहाल रखी। अब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मीडिया में इसके खिलाफ़ इतना ज्यादा शोर मचने लगा कि सरकार को कार्रवाई का नाटक करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह सच है कि न्यायपालिका में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार पैदा हो गया है कि अब आम लोग़ों का विश्वास इस पर नहीं रहा। निर्मल यादव तो हाई कोर्ट की एक मामूली जज थीं, पर जहां भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हो और इसके बावजूद मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की ऊंची कुर्सी पर बैठा हो, वहां निर्मल यादव जैसी घूसखोर जज को कोई सजा मिलने वाली नहीं है। क्या सरकार निर्मल यादव से रिश्वत के 15 लाख रुपये वसूल कर लेगी? हर्गिज नहीं। निर्मल यादव को कटघरे में लाना जनता का न्यायपालिका पर विश्वास बनाये रखने का एक असफल प्रयास भर है। श्रम मंत्री ने ईएसआई अस्पतालों में सुधार की घोषणा तो जरूर की है, पर सिर्फ़ घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। घोषणा को अमल में भी लाना होगा। यह श्रम मंत्री के बूते की बात नहीं है। मुख्यमंत्री हुड्डा ने सारे अधिकार अपने हाथों में रख रखे हैं। हुड्डा ग़रीब विरोधी और अमीर समर्थक हैं। वे ईएसआई अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों की दशा कतई नहीं सुधरने देंगे। ऐसा लगता है कि प्राइवेट पंचतारा अस्पतालों के संचालक हुड्डा को पैसे पहुंचाते हैं ताकि वे सरकारी अस्पतालों की दशा न सुधरने दें, क्योंकि अगर सरकारी अस्पतालों और ईएसआई अस्पतालों की दशा सुधर गई तो पंचतारा अस्पतालों को घाटा उठाना पड़ सकता है। आपने 'हर शाख पर उल्लू बैठा है' में बजट के प्रावधानों का उल्लेख कर सारी सच्चाई स्पष्ट कर दी है। जहां तक नगर निगम का सवाल है, इसकी दशा कभी सुधरने वाली नहीं है। नगर निगम में चाहे जितना पैसा झोंक दिया जाये, उसका जनता को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बजट पर आपने अच्छी सामग्री छापी है। 'भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता' लेख काफ़ी अच्छा लगा। बाल यौन शोषण पर लेख भी ठीक है। बाबा रामदेव को अब राजनीति का शौक चर्राया है। पर राजनीति के मैदान में उतरते ही उन्हें आटे-दाल का भाव पता चल जायेगा। कुल मिला कर यह अंक बहुत ही अच्छा लगा।

- कृपाशंकर, फ़रीदाबाद

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। रिश्वतखोर जज निर्मल यादव कटघरे में आ ही गई। पर इस देश में न जाने कितने रिश्वतखोर जज हैं। यह तो बेचारी चपरासी की ग़लती से पकड़ में आ गई, नहीं तो किसे पता चलता कि इन्होंने 15 लाख की घूस ली है। इसके अलावा इन्होंने अपनी सेवा के दौरान कितनी घूस ली होगी, इसका किसे पता? अब इन पर कार्रवाई होगी। पर उसी वक्त क्यों नहीं हुई जब यह मामला सामने आया। उस समय तो इनका बाइज्जत तबादला कर दिया गया और एक घूसखोर जज को फ़ैसले सुनाने का अधिकार दे दिया गया। आख़िर यह न्याय तंत्र के साथ एक भद्दा मजाक था या नहीं? इन्हें तो उसी वक्त इसे महत्त्वपूर्ण पद से हटा देना चाहिए था। पर सरकार और न्याय तंत्र में बैठे लोग़ों ने इन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की। अब भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बस कार्रवाई का एक नाटक होगा। ऐसे रिश्वतखोर जज को सलाखों के पीछे डालना चहिए और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल समाप्त करना चाहिए। आज भारतीय न्याय व्यवस्था से आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है। ऐसे जज बहुत ही कम हैं जो ईमानदारीपूर्वक अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करते हों। जहां तक श्रम मंत्री द्वारा ईएसआई अस्पतालों की दशा सुधारने का सवाल है तो यह काम तो तब होगा जब इसके लिए राज्य सरकार बजट आवंटन करे। राज्य सरकार ने जो बजट आवंटित किया है, उसे आपने छाप ही दिया है। फ़िर आम जनता यह उम्मीद कैसे करे कि ईएसआई अस्पतालों की दशा सुधरेगी। दूसरी बात यह है कि हुड्डा सरकार में कुछ मंत्रियों की चलती है। पं.शिवचरण लाल शर्मा की कुछ भी नहीं चलती। हुड्डा तानाशाह प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनका ध्यान सिर्फ़ अपने हित पर है, जनता के हित पर नहीं। अगले चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखायेगी। नगर निगम की खस्ता हालत पर आपने जो कुछ लिखा है, ठीक ही लिखा है। इस सफ़ेद हाथी पर जितना खर्च किया जायेगा, सब बेकार ही होगा। उससे जनता को कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है। हरिशंकर परसाई का व्यंग्य 'विज्ञापन में बिकती नारी' काफ़ी अच्छा लगा। भगत सिंह पर प्रकाशित लेख भी बढ़िया है। इससे पता चलता है कि भगत सिंह की विचारधारा क्या थी और किस प्रकार वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। बजट पर प्रकाशित सामग्री अच्छी लगी।

-राजीव दुग्गल, फ़रीदाबाद

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। इस अंक में काफ़ी महत्त्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन हुआ है। जहां तक रिश्वतखोर जज निर्मल यादव के कटघरे में जाने का प्रश्न है, यह काम बहुत ही पहले होना चाहिए था। पर ऐसा न करके शासकों ने अपने जनविरोधी चरित्र का ही परिचय दिया है। अब भी इस रिश्वतखोर जज का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे-ऐसे न जाने कितने रिश्वतखोर जज भारतीय न्यायपालिका का गौरव बढ़ा रहे हैं। भगत सिंह पर लिखा लेख अच्छा लगा। आज भगत सिंह की विचारधारा के प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है। जहां तक बाल यौन शोषण की समस्या है, पूंजीवादी समाज-व्यवस्था में यह खत्म होने वाली नहीं है, सरकार चाहे लाख कानून बना ले। बजट पर संतुलित लेख का प्रकाशन आपने किया है। आपने इसके पहले अंक में यह छापा था कि ईएसआई निगम मज़दूरों का शोषण कर रहा है। अब मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि ईएसआई अस्पतालों की दशा सुधारी जायेगी। पर सिर्फ़ कहने से तो कुछ नहीं होता। आपने सरकार का बजट-प्रावधान भी छाप रखा है, इससे स्पष्ट होता है कि ईएसआई अस्पतालों की दशा में कोई सुधार नहीं होगा। इसी तरह नगर निगम की व्यवस्था में भी कोई सुधार संभव नहीं है, क्योंकि सारे अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्ट हैं। पार्षद भी अफ़सरों के आगे-पीछे घूमने वाले हैं। अन्य सामग्री भी ठीक है।

- अमित गोयल, गुड़गांव